विमुद्रीकरण

एक बहु-आयामी सफलता

INDIA

विषय-सूची

1 भारत हुआ डिजिटल 1

2 भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी गतिविधियों पर करारा प्रहार 9

3 काले धन के खिलाफ युद्ध 15

4 बेहतर प्रक्रिया अनुपालन, कर संग्रह में वृद्धि 21

5 विमुद्रीकरण के अन्य लाभ 29

हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या में युवा है। ऐसे में, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमारे लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में भारत जैसे देश को अन्य सभी से आगे रहना चाहिए। हमारे युवाओं को 'स्टार्ट-अप्स' से काफी लाभ हुआ है। डिजिटल मूवमेंट हमारे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्हें अपने नए विचारों, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के साथ इसमें पूरी ताकत के साथ भाग लेना चाहिए। लेकिन हमें काले धन और भ्रष्टाचार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए अभियान से भी जुड़ना चाहिए।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय 1

भारत हुआ डिजिटल

बढ़े डिजिटलीकरण से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लाभ

2016 में लॉन्च किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को विमुद्रीकरण के बाद बढ़े डिजिटल लेन-देन से जबरदस्त लाभ हुआ।

2016-17 में यूपीआई के जरिए 6,952 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, 2017 में यह बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपये, 2018 में 8.7 लाख करोड़ रुपये और 2019-20 में 21 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। यूपीआई से 189 बैंक जुड़े हैं और अक्टूबर 2020 तक यूपीआई के माध्यम से 29 अरब से अधिक के लेन-देन हो चुके हैं।

यूपीआई लेन-देन की संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने में 16 महीने लगे; हालांकि अगले 16 महीनों में यह संख्या 8 गुना बढ़कर 10 करोड़ से 80 करोड़ हो गई।

यूपीआई लेन-देन में यह वृद्धि और आगे बढ़ी और 20

महीने के भीतर लेन-देन की संख्या 80 करोड़ से 200 करोड़ हो गई।

यूपीआई पर लेन-देन की संख्या में तेजी से वृद्धि

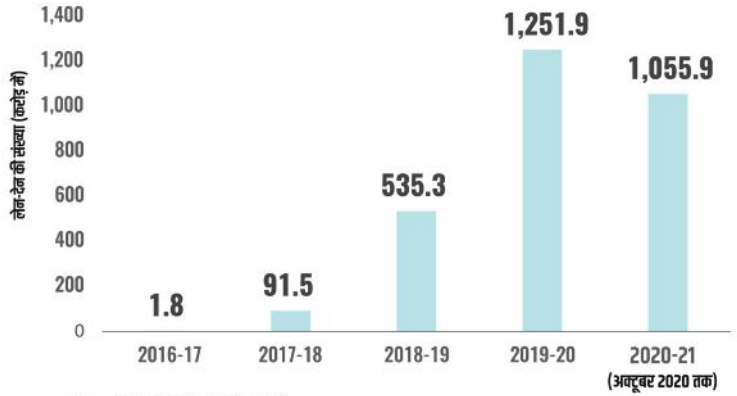

स्रोत: एनपीसीआई और आरबीआई के आंकड़े

यूपीआई पर लेन-देन कई गुना बढ़ा

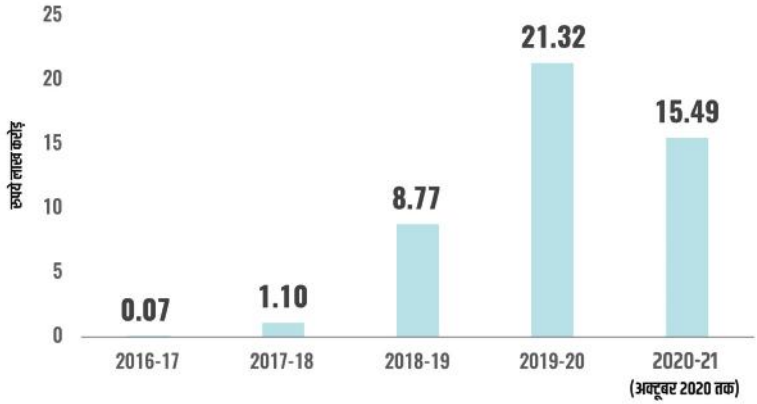

अक्टूबर 2020 में यूपीआई पर
मासिक लेन-देन

2 अरब

के आंकड़े को पार कर गया, जो
संख्या में अक्टूबर 2019 से

80 प्रतिशत की वृद्धि

और लेन-देन मूल्य में

101 प्रतिशत की बढ़ोतरी

को दिखाता है।

यूपीआई लेन-देन में 80% बढ़ोतरी साल-दर-साल (मिलियन)

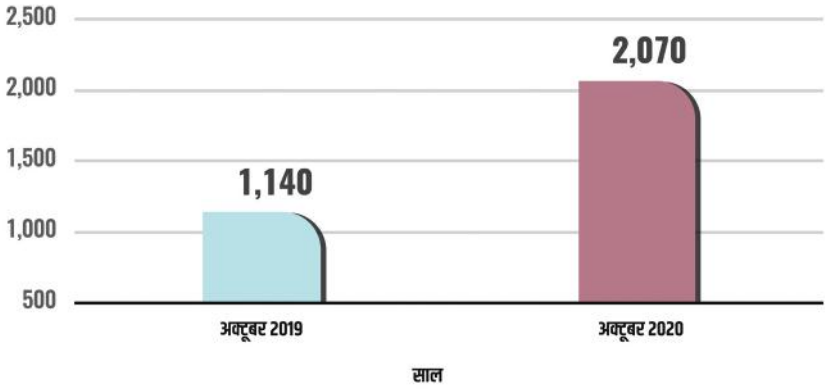

यूपीआई लेन-देन मूल्य दोगुना साल-दर-साल (करोड़ रुपये)

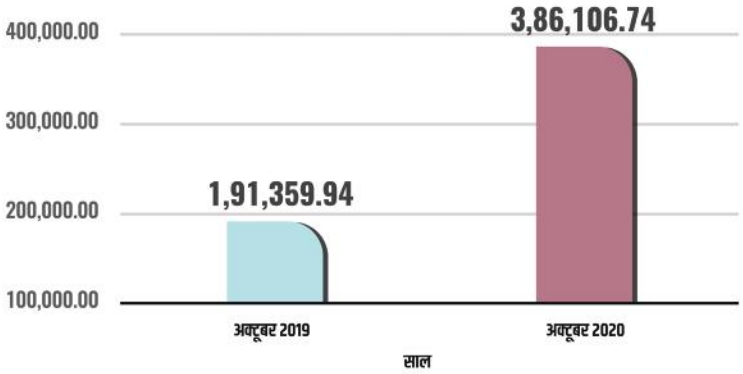

UPI
TRANSFER MONEY
Send
Receive
Scan & Pay
MY INFORMATION
Transactions
Profile
Accounts

कम नकद आधारित अर्थव्यवस्था - विमुद्रीकरण से पैदा हुआ अंतर

वित्त वर्ष 2015-16 के अंत में 16.41 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जो 2014-15 में 14.51% की साल-दर-साल की वृद्धि को दर्शाता है।

इस रफ्तार से 2019-20 के अंत तक प्रचलित नोटों में वृद्धि 298.49 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई होती।

हालांकि, यह 2019-20 के अंत तक केवल 24.20 लाख करोड़ तक बढ़ा।

इससे पता चलता है कि विमुद्रीकरण के बाद डिजिटलीकरण ने प्रचलन में मुद्रा की वृद्धि को 4.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक कम करने में सफलता पाई।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस
Read to Lead

अगर विमुद्रीकरण न होता, तो भारत में अब तक काफी नक़दी बढ़ जाती; नोटबंदी ने नकदी में वृद्धि को धीमा किया।

3 जनवरी, 2020 2:11 PM

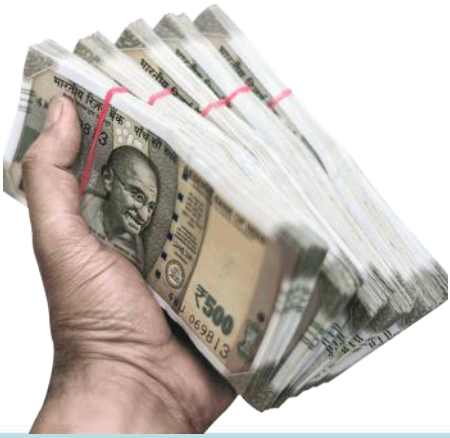

प्रचलन में कम हुए कुल करंसी नोट

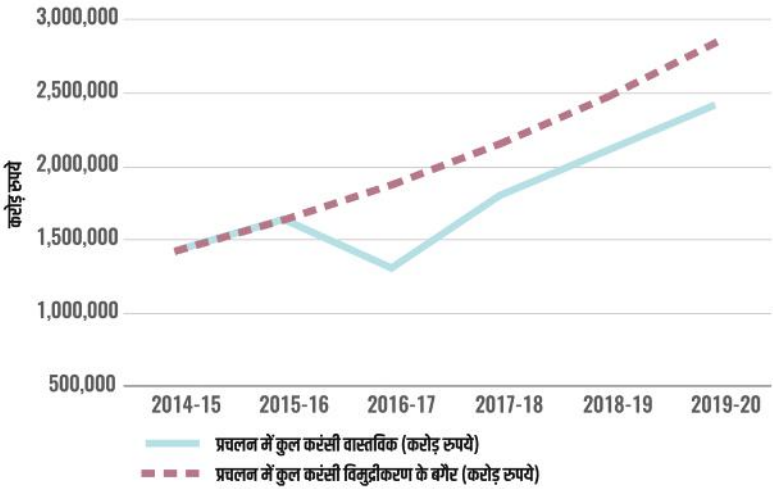

स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2020, शीतकालीन सत्र जनवरी 2020 में वित्त मंत्री के जवाब के आधार पर की गई गणना, जिसको 3 जनवरी 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया।

भ्रष्टाचार इन सभी प्रणालियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। एक तरफ, भ्रष्टाचार देश के विकास को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार देश के सामाजिक संतुलन को भी नष्ट करता है, और सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार देश की व्यवस्था और उसके प्रति लोगों के अपनेपन की भावना और विश्वास को कमजोर करता है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय 2

भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी गतिविधियों पर करारा प्रहार

विमुद्रीकरण का तत्काल प्रभाव- अघोषित आय का पता चला

नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान, जांच में 636 करोड़ रुपये नकद समेत 900 करोड़ रुपये जब्त किए गए और 7,961 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

1 अप्रैल 2017 और 30 सितंबर 2020 के बीच आयकर विभाग ने 2,632 मामलों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 3,950 करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित संपत्ति जब्त की गई और 45,218 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

कर चोरी करने वालों पर नकेल, बड़ी विसंगतियों का खुलासा

नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान 8,239 सर्वेक्षणों से 6,745 करोड़ रुपये की अघोषित आय के बारे में जानकारी मिली।

अप्रैल 2017 और अगस्त 2020 की अवधि के दौरान 41,708 मामलों की जांच की गई जिसमें 48,188 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

नकली नोटों में गिरावट

विमुद्रीकरण के बाद पता चलने वाले नकली नोटों की कुल संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई।

नए नोट आने से फर्जी करंसी का पता लगाना आसान हुआ, जिससे कार्रवाई भी तेज हुई।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि- आतंक के वित्तपोषण और वामपंथी उग्रवाद के वित्तपोषण के स्रोत पता लगा।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण पर ब्रेक लगा।

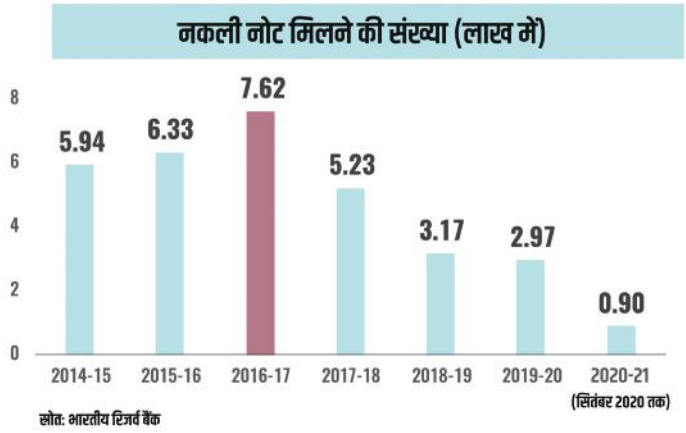

क्लीन मनी, क्लीनर इकोनॉमी, विमुद्रीकरण को धन्यवाद

विमुद्रीकरण के बाद ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया गया था; संदिग्ध मामलों की पहचान के लिए नोटबंदी के दौरान नकद जमा डेटा का विश्लेषण किया गया।

करीब 17.92 लाख लोगों को आगे सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया; लगभग 11.85 लाख लोगों ने इस पर ऑनलाइन जवाब दिए।

ऐसे 3.04 लाख लोगों की पहचान की गई, जिन्होंने 10 लाख या उससे अधिक की नकदी जमा की, लेकिन रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि तक इसे फाइल नहीं किया।

रिटर्न फाइल न करने वाले 2.09 लाख लोगों ने जवाब दिए और इन लोगों ने स्व-मूल्यांकन कर के रूप में 6,531 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

कुल मिलाकर रिटर्न फाइल न करने वाले लोगों की तुलना में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान स्व-मूल्यांकन कर द्वारा किया गया।

बेनामी संपत्तियों और शेल कंपनियों का खुलासा

सितंबर 2020 के अंत तक 13,400 करोड़ मूल्य की बेनामी संपत्तियां संलग्न की गई; 458 मामलों में नोटिस भी जारी किए गए जिसमें 14,150 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्तियां और आय का पता चला।

अप्रैल 2020 तक 3.82 लाख शेल कंपनियों का पता लगाकर उनका पंजीकरण निरस्त किया गया, जबकि 4.52 लाख निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया।

कई लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा ताकि देश को धोखा देने वाले मुट्ठीभर लोगों की पहचान की जा सके। जब करदाताओं की संख्या को गर्व के साथ बढ़ाया जाना चाहिए था, तब मिलीभगत और मौन सहमति की एक प्रणाली उभरकर सामने आई। ऐसे माहौल में काले और सफेद धन का उद्योग भी खूब फला-फूला। ईमानदार व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के बजाय इस सिस्टम ने ईमानदार व्यवसायियों, नियोक्ताओं और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को कुचल दिया।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय 3

काले धन के खिलाफ युद्ध

काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी है

2 लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध; धारा 80जी के तहत कोई कटौती नहीं, यदि नकद दान 2,000 रुपये से अधिक है, अप्रैल 2018 से प्रभावी।

राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से अधिक के नकद चंदे देने पर प्रतिबंध।

उद्धृत शेयरों के अलावा शेयरों के हस्तांतरण के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए बाजार मूल्य को पूरा मूल्य माना जायेगा।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास सावधि जमा और साधारण बैंक बचत खाता के अलावा किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में कोई अन्य खाता है, तो उसे अपना पैन या फॉर्म नंबर 60 आदि प्रस्तुत करना होगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने और नए पैन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना।

काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का प्रभाव

अधिनियम जुलाई, 2015 में लागू हुआ।

3 महीने के भीतर, 644 घोषणाकर्ताओं ने 4,164 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्ति का खुलासा किया और टैक्स व जुर्माने के रूप में 2,476 करोड़ रुपये चुकाए।

सितंबर 2020 के अंत तक, 14,150 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति और आय के मामलों में नोटिस जारी किए गए।

काले धन से जुड़े मामलों में कानून की पूरी ताकत लगाना

30 सितम्बर, 2020 तक एचएसबीसी मामले में की गई कार्रवाई:

8,465 करोड़ रुपये की अघोषित आय को टैक्स के दायरे में लाया गया और 1,294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया

89 मामलों में 204 मुक़दमे दायर किये गये।

30 सितम्बर, 2020 तक आईसीआईजे मामले में की गई कार्रवाई:

11,010 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

58 मामलों में 99 मुक़दमे दायर किये गये।

30 सितम्बर, 2020 तक पनामा पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई:

81 मामलों में तलाशी तथा जब्ती और/या सर्वेक्षण।

65 मामलों में काला धन अधिनियम की धारा 10 के तहत नोटिस जारी किये गये।

46 मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज किये गये।

1575 करोड़ रुपये (लगभग) के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला।

30 सितम्बर, 2020 तक पैराडाइज पेपर्स लीक मामले में की गई कार्रवाई:

31 मामलों में तलाशी तथा जब्ती और/या सर्वेक्षण।

59 मामलों में काला धन अधिनियम की धारा 10 के तहत नोटिस जारी।

13 मामलों में आपराधिक अभियोजन की शिकायतें दर्ज/शुरू की गईं।

207 करोड़ रुपये के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला।

घरेलू काले धन के खिलाफ कार्रवाई

अप्रैल, 2014 से अगस्त-सितम्बर 2020 तक की अवधि के दौरान:

4,776 मामलों में तलाशी की कार्रवाई हुई।

6,894 करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित संपत्ति जब्त की गयी।

82,168 करोड़ रुपये की अघोषित आय को स्वीकार किया।

63,691 मामलों में सर्वेक्षण किए गए; 84,396 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

12,224 मामलों में मुक़दमे दर्ज किये गये।

9070 मामलों को सुलह के बाद निपटाया गया।

327 व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया।

सरकार को जो टैक्स मिलता है, उसका उपयोग लोक कल्याण योजनाओं तथा देश में ढांचागत संरचना में सुधार के लिए किया जाता है। टैक्स के पैसे से देश में नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता है, नए राजमार्ग बनाए जाते हैं और मेट्रो का काम होता है। निःशुल्क गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, सस्ता राशन, गैस सब्सिडी, पेट्रोल-डीजल सब्सिडी, छात्रवृत्ति- सरकार इसलिए इतना सब कुछ कर पा रही है क्योंकि देश के कुछ जिम्मेदार नागरिक ईमानदारी से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय 4

बेहतर प्रक्रिया अनुपालन, कर संग्रह में वृद्धि

विमुद्रीकरण से प्रत्यक्ष कर को सही दिशा में गति मिली

2018-19 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2016-17 के संग्रह से 35% अधिक है।

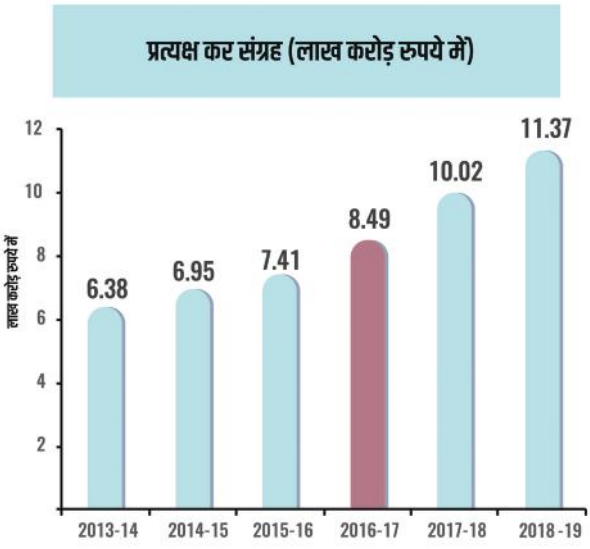

2017-18 की कर संग्रह वृद्धि दर, पिछले सात वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक थी - 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर अग्रिम कर संग्रह में 23.4% और स्व-मूल्यांकन कर में 29.2% की वृद्धि हुई।

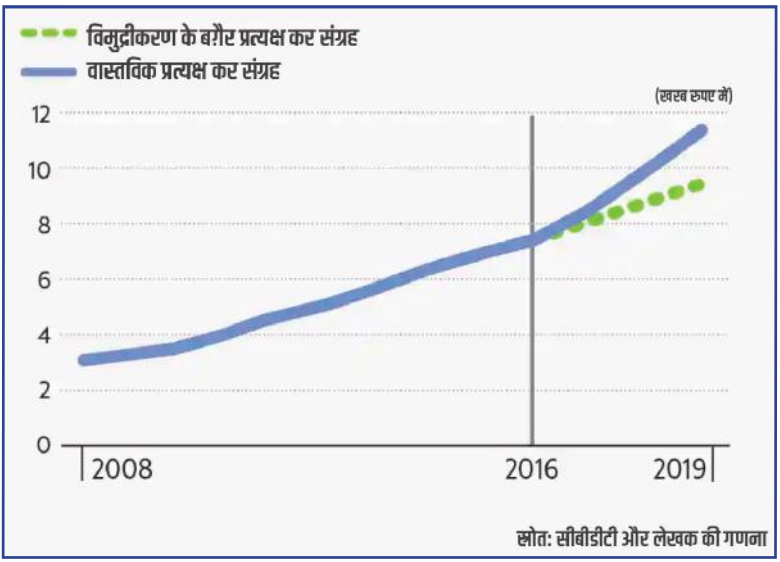

पिछला ग्राफ़ 2008 से तैयार किया गया है। नीचे दिया गया चार्ट 2013-14 से तैयार किया गया है, जो केंद्र में मोदी सरकार के पदभार संभालने के साथ हुए बदलाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

यह आवश्यक है क्योंकि यह कम समय में साहसपूर्ण कदमों के साथ रुझान को बदलने में निर्णयों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

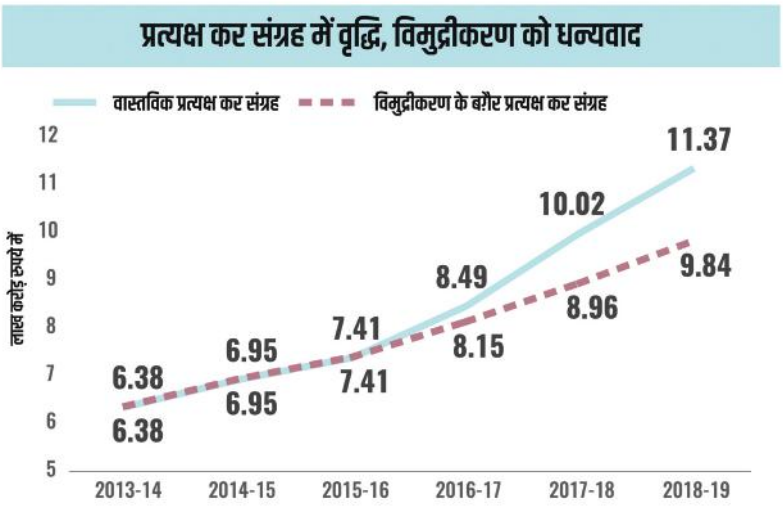

ग्राफ को LiveMint में प्रकाशित मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार केवी सुब्रमण्यम के लेख से लिया गया है।

विमुद्रीकरण से टैक्स आधार में वृद्धि, अनुपालन नहीं करने वालों की संख्या में कमी आयी

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आयकर विभाग में 6.86 करोड़ आईटी रिटर्न दाखिल किए गए; यह वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दाखिल किए गए 5.48 करोड़ आईटी रिटर्न से 25% अधिक है।

यह वित्त वर्ष 2017-18 के पिछले पांच वर्षों में हासिल की गई सबसे अच्छी विकास दर में से एक थी।

दाखिल किये गए रिटर्न की संख्या में लगातार वृद्धि दर्शाती है कि यह वृद्धि केवल एक बार के लिए नहीं थी।

दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या (करोड़ में)

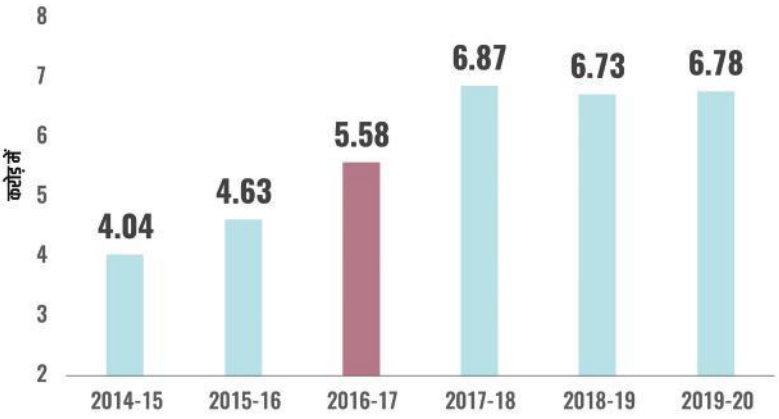

आयकर विभाग टाइम सीरीज़ का आंकड़ा

रिटर्न दाखिल करने वाले नए लोगों की संख्या बढ़ी, यह न्यू इंडिया की अर्थव्यवस्था में विश्वास को प्रदर्शित करता है

2015-16 के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले नए लोगों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि, इसके लिए विमुद्रीकरण को धन्यवाद

2017-18 में आईटी रिटर्न दाखिल करने वाले 1.07 करोड़ नए लोग जुड़े; वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईटी रिटर्न दाखिल करने वाले 1.1 करोड़ नए लोग जुड़े।

इसके अलावा, रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 के 5.4 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 6.3 करोड़ हो गयी।

पिछले कुछ वर्षों में आयकर दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

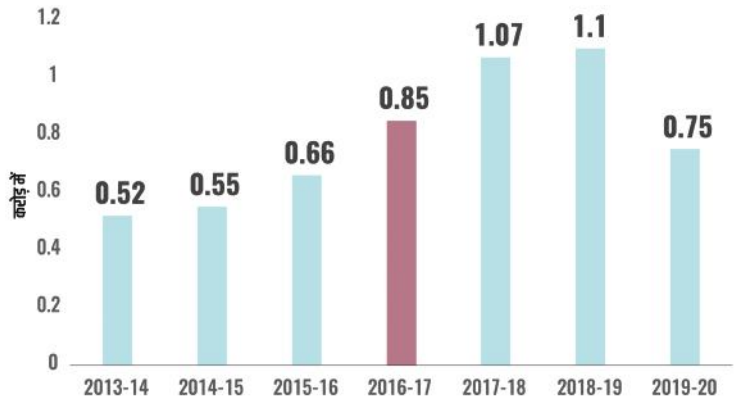

आयकर विभाग टाइम सीरीज़ का आंकड़ा

2016-17 के बाद से कुल मिलकर 3.77 करोड़ नए आईटी रिटर्न दाखिल करने वाले जुड़े, यह 2013-14 और 2015-16 के बीच नए आईटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या से दोगुनी है।

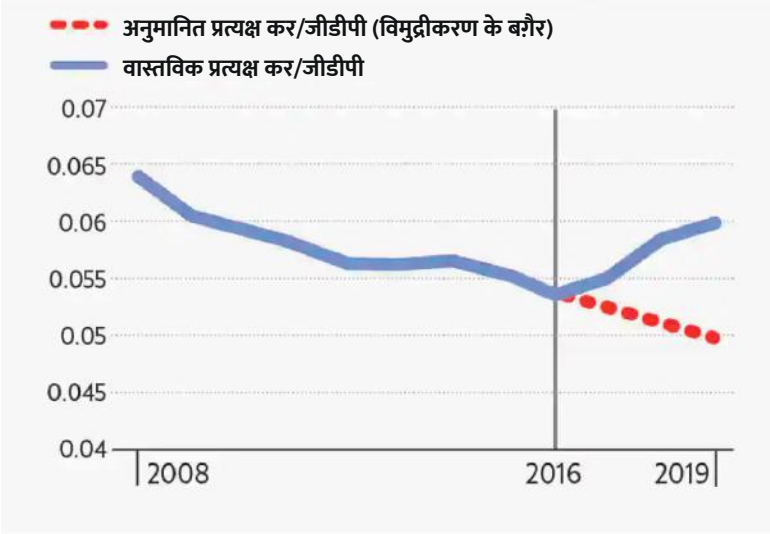

ग्राफ को LiveMint में प्रकाशित मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार केवी सुब्रमण्यम के लेख से लिया गया है।

विमुद्रीकरण से कॉर्पोरेट और अनुपालन में समन्वय बेहतर हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा 8.03 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की संख्या 17% से अधिक की वृद्धि के साथ 9.42 लाख से अधिक हो गयी; 2018-19 में यह आंकड़ा 9.64 लाख को पार कर गया।

2013-14 की तुलना में 2018-19 में कॉर्पोरेट करदाता रिटर्न की संख्या 35% अधिक है, जो इस कदम की सफलता को रेखांकित करती है।

दाखिल किए गए कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न (लाख में)

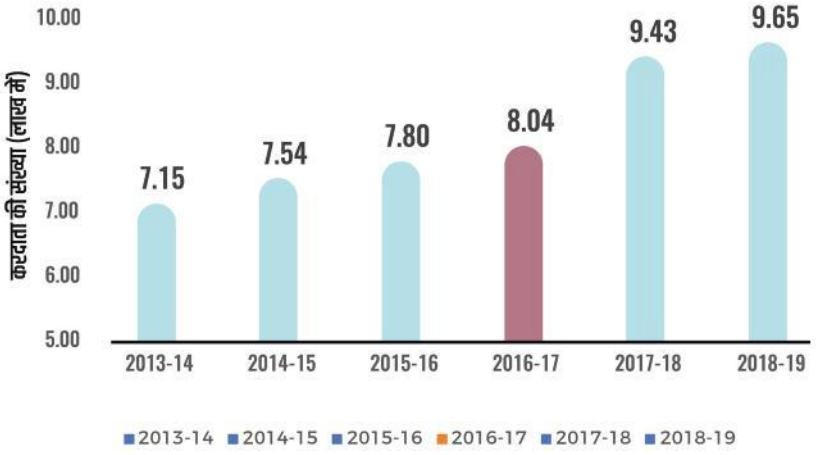

भाइयों और बहनों, अनौपचारिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारे जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों को अपने श्रम और कड़ी मेहनत का भुगतान नकद में किया जाता है। उनके वेतन का भुगतान नकद में किया जाता है और हम जानते हैं कि इस कारण उनका शोषण भी होता है। यदि उन्हें 100 रुपये प्राप्त करने हैं, तो उन्हें केवल 80 रुपये मिलते हैं, अगर उन्हें 80 रुपये का भुगतान किया जाना है, तो वे केवल 50 रुपए पाते हैं। वे बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं से भी वंचित हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय 5

विमुद्रीकरण के अन्य लाभ

विमुद्रीकरण के कारण वित्तीय लाभ

प्रोफेसर चंदा और प्रोफेसर कुक (2020) द्वारा लिखित 'क्या भारत का विमुद्रीकरण पुनर्वितरण से संबंधित था? उपग्रहों और सर्वेक्षणों की अंतर्दृष्टि' के शीर्षक शोध-पत्र के अनुसार, विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में सबसे गरीब घरों के खर्च और आय में जहां उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वहीं सभी परिवारों की आय और व्यय में विमुद्रीकरण के बाद वृद्धि हुई है।

इस शोध– पत्र ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत के विमुद्रीकरण के प्रयोग के मध्यम अवधि के प्रभाव काफी भिन्न थे और यह अल्पकालिक विघटन के ध्रुवीय विपरीत नहीं थे। विमुद्रीकरण के इन विस्तारवादी प्रभावों को अपरिष्कृत सकल आंकड़ों, रात के समय की रोशनी से लेकर घर की आय और व्यय, तक में देखा जा सकता है।

वास्तविक घरेलू आय और व्यय (उपभोक्ता पिरामिड)

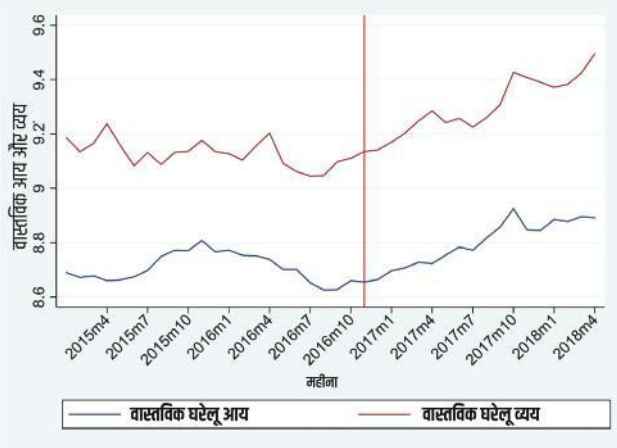

सारांश एवं टिप्पणियां: उपभोक्ता पिरामिड सर्वेक्षण से निकला यह आंकड़ा घरेलू व्यय और आय को दर्शाता है। सीपीआई (आधार 2012 = 100) का उपयोग करके इन आंकड़ों से प्राप्त विभिन्न मान को अपस्फीति किया जाता है। सर्वेक्षण भार का उपयोग आकृति में दर्शाए गए औसत मूल्यों पर पहुँचने के लिए किया गया।

सौजन्य: अरिंदम चंदा और सी. जस्टिन कुक की एक रिपोर्ट

सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए; विमुद्रीकरण ईपीएफओ और ईएसआईसी के ग्राहकों के आधार में एक उछाल लेकर आई

विमुद्रीकरण ने अधिक आर्थिक औपचारिकता को बढ़ावा दिया।

औपचारिक नौकरियों के सृजन और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए धन्यवाद, अन्यथा ये सब नहीं हो पाता।

सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के दौरान, ईपीएफओ के साथ 1.1 करोड़ नए लोग जुड़े।

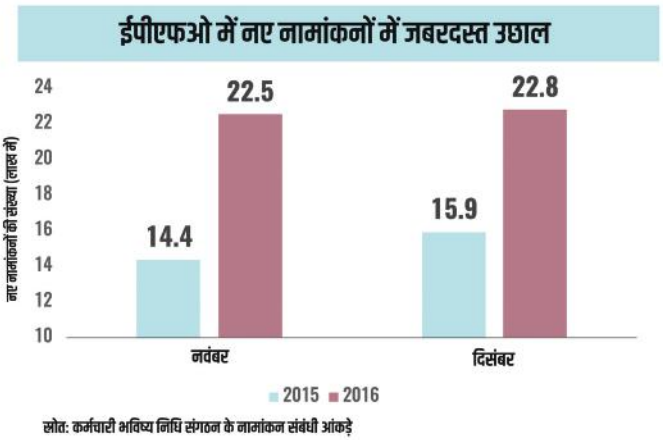

स्रोत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नामांकन संबंधी आंकड़े

वर्ष 2017-18 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के पंजीकरण में 55% की वृद्धि हुई।

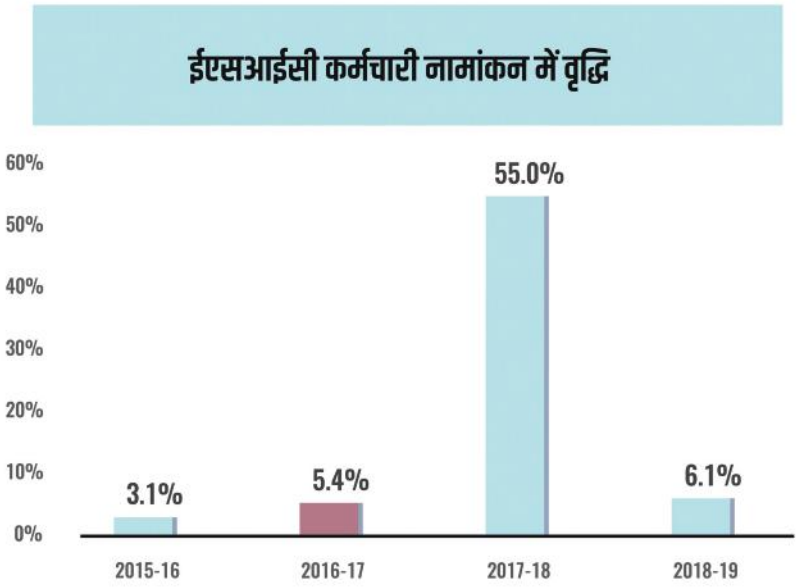

ईएसआईसी द्वारा कवर किए गए बीमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

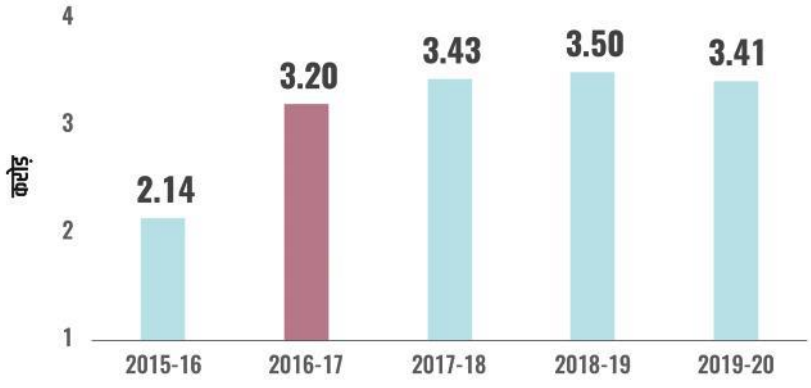

स्रोत: ईएसआईसी के नामांकन संबंधी आंकड़े

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार